पहलः सरकार स्टार्टअप को बढ़ावा देगी, एक लाख करोड़ रुपये का कोष बनेगा, लंबी अवधि के लिए ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा

तकनीक के क्षेत्र में अनुसंधान से बदलेगी तस्वीर

युवा

नई दिल्ली, एजेंसी। देश में तकनीक के क्षेत्र का स्वर्णिम युग शुरू होगा। सरकार तकनीक से जुड़े स्टार्टअप को अनुसंधान और नवाचार के लिए एक लाख करोड़ रुपये मुहैया कराएगी। ब्याज मुक्त या कम ब्याज दर पर कोष वितरित किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को बजट भाषण में यह घोषणा की।

निर्मला सीतारमण ने कहा, उभरते हुए क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के अनुसंधान प्रयासों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से एक लाख करोड़ का कोष बनेगा। इसमें 50 वर्ष का ब्याज रहित ऋण दिया जाएगा। इससे निजी क्षेत्र को रिसर्च और इनोवेशन पहल करने को प्रोत्साहन मिलेगा। ऐसे कार्यक्रम जरूरी हैं जो हमारे युवाओं की शक्ति को प्रौद्योगिकी से मिला सकें। भारत के प्रौद्योगिकी पसंद करने वाले युवाओं के लिए यह एक स्वर्णिम युग है।

'जय अनुसंधान' : निर्मला सीतारमण ने लालबहादुर शास्त्री के दिए गए नारे जय जवान, जय किसान को दोहराया। उन्होंने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान का नारा दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे और विस्तार देते हुए 'जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान' का नारा दिया है।

डीप टेक से 'आत्मनिर्भरता' : वित्त मंत्री ने डीप टेक तकनीकों पर भी चर्चा की। इसके तहत रक्षा क्षेत्र में 'आत्मनिर्भरता' हासिल करने के लिए डिप टेक तकनीकों पर काम किया जाएगा। बता दें कि डीप टेक को एडवांस तकनीक भी कहा जाता है। डीप टेक में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

50 वर्ष का ब्याज रहित ऋण दिया जाएगा योजना के तहत

1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण दिया कौशल भारत मिशन के तहत

20 केंद्रीय मंत्रालयों-विभागों के माध्यम से लागू हो रहीं कौशल विकास योजनाएं

स्टार्टअप को ये राहत भी...

स्टार्टअप द्वारा किए गए निवेश पर कर प्रोत्साहन को मार्च, 2025 तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि स्टार्टअप द्वारा किए गए निवेश के लिए कुछ कर लाभ और साथ ही कुछ आईएफएससी (अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र) इकाइयों की कुछ आय पर कर छूट 31 मार्च, 2024 को समाप्त हो रही है। कराधान में निरंतरता प्रदान करने के लिए तारीख को 31 मार्च, 2025 तक बढ़ाने का प्रस्ताव कर रहे हैं। स्टार्टअप इकाइयां स्टार्टअप इंडिया के लिए एक कार्ययोजना के तहत आयकर लाभ जैसे कर प्रोत्साहन का लाभ उठा सकती हैं।

1.17 लाख स्टार्टअप को मान्यता दी जा चुकी अब तक

केंद्र की प्रमुख योजनाओं का आवंटन बढ़ा

वित्त मंत्री की ओर से गुरुवार को पेश किए गए अंतरिम बजट में वित्तीय वर्ष 2024-25 में मनरेगा, आयुष्मान भारत, सौर ऊर्जा सहित कई प्रमुख योजनाओं का आवंटन बढ़ा दिया गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में पहले 60000 करोड़ रुपये आवंटित थे, अब इसे बढ़ाकर 86000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 तथा 2024-25 में प्रमुख योजनाओं पर बजट आवंटन का ब्योरा...